

देश का रबर उत्पादन घटा खपत 12 प्रतिशत तक बढ़ी

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 मार्च

इस साल के पहले 10 महीनों के दौरान प्राकृतिक रबर की खपत 12 प्रतिशत तक बढ़कर 10.2 लाख टन के आंकड़े को पार कर गई। घरेलू आपूर्ति की किल्लत से परेशान टायर निर्माताओं ने रबर के लिए आयात शुल्क घटा कर 10 प्रतिशत से कम किए जाने और इसकी उपलब्धता आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।

रबर बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में खपत अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में 10.2 लाख टन के आंकड़े पर पहुंच गई जो पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि में 9.13 लाख टन पर थी। वहीं उत्पादन अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान 5.6 लाख टन पर दर्ज किया गया जो पिछले साल की समान अवधि के 5.97 लाख टन की तुलना में कम है।

पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए उत्पादन-खपत अंतर 3.16 लाख टन था जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 4.63 लाख टन हो गया है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष की पहली छमाही में केरल में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ था और अक्टूबर-जनवरी का व्यस्त सीजन भी अपेक्षित उत्पादन में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू रबर की किल्लत पैदा हुई।

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को भेजे एक पत्र में टायर उद्योग की संस्था ने उपभोक्ता हितों के लिए रबर की उपलब्धता आसान बनाने की मांग की है।

ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के महानिदेशक राजीव बुधराजा



अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में रबर की खपत में वृद्धि दर्ज की गई

ने कहा, 'पहली बार भारत में रबर खपत वित्त वर्ष के शुरूआती 10 महीनों में 10 लाख टन के पार पहुंची है। औसत मासिक खपत एक लाख टन दर्ज की गई। देश में उत्पादन वृद्धि के लिए टायर उद्योग की प्रतिबद्धता को कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि से मदद मिल सकती है, वरना घरेलू निर्माताओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हो जाएगी।'

भारत में रबर खपत वर्ष 2018-19 के लिए 12 लाख टन के रबर बोर्ड के अनुमान को पार पहुंचने की संभावना है। घरेलू रबर उत्पादन देश में कुल रबर खपत का 55 प्रतिशत हिस्सा पूरा करने में ही सक्षम है और रबर उपभोग उद्योग के लिए आयात पर निर्भरता पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत तक बढ़ी है। एसोसिएशन के अनुसार, रबर का आयात टायर संयंत्रों के संचालन के लिए जरूरी है। हालांकि नीतिगत परिवेश काफी सख्त है। रबर आयात पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत पर है, जो किसी अन्य रबर आयातक देश द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क की तुलना में काफी ज्यादा है।